दैनिक जागरण

दायित्व बोध जीवन को सार्थक बनाने की पहली कड़ी है

नागरिकता विधेयक

संसद के शीतकालीन सत्र के पहले आयोजित सर्वदलीय बैठक के जरिये इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इस दौरान दोनों सदनों का माहौल कैसा रहने वाला है? इस तरह की बैठकें औपचारिक ही अधिक होती हैं और यह कहना कठिन है कि वे सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच कोई समझबूझ विकसित करने में सहायक बनती हैं। सरकार ने संकेत दिया है कि वह संसद के आगामी सत्र में करीब दो दर्जन विधेयकों को पेश और पारित करने का इरादा रखती है। इसी के साथ विपक्ष ने भी उन मुद्दों को रेखांकित किया है जिन्हें उसकी ओर उठाया जा सकता है। सभी जरूरी मसलों पर संसद में चर्चा की मांग करना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन इस अधिकार के नाम पर संसद को अखाड़ा बनाने से बचा जाना चाहिए। जब विपक्ष हंगामा करने पर अड़ जाता है तब फिर यह दलील भोथरी ही साबित होती है कि संसद चलाना सत्तापक्ष की जिम्मेदारी है। संसद के आगामी सत्र में जिन विधेयकों को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष में ठन सकती है उनमें नागरिकता संबंधी संशोधन विधेयक प्रमुख है। इस विधेयक को लेकर पक्ष और विपक्ष के मतभेद किसी से छिपे नहीं, लेकिन जरूरत इसकी है कि दोनों पक्ष इस विधेयक को लेकर सहमति कायम करें।

नागरिकता संशोधन विधेयक, 1955 के नागरिकता अधिनियम के कुछ प्रावधानों को बदलने के लिए पेश किया जा रहा है। सरकार ऐसे प्रावधान चाहती है जिससे बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि देशों से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई के लिए भारत की नागरिकता हासिल करना आसान हो जाए। विपक्षी दलों को इस पर आपत्ति है। स्वाभाविक रूप से उनकी आपत्ति पड़ोसी देशों के मुस्लिम को बाहर रखने पर है। पहली नजर में यह आपत्ति सही जान पड़ती है, लेकिन क्या इस सच की अनदेखी की जा सकती है कि इन देशों में जो प्रताड़ित हो रहे हैं वे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी आदि ही हैं? इस तथ्य की भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ ने किस तरह असम समेत पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों की सामाजिक संरचना को बदल दिया है। कुछ स्थानों पर तो बाहर से आए लोगों की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि स्थानीय संस्कृति ही खतरे में पड़ गई है। चूंकि नागरिकता संशोधन विधेयक का विरोध असम में भी हो रहा है इसलिए सरकार को विपक्ष के साथ वहां के लोगों को भी भरोसे में लेना होगा। विपक्षी दल इस विधेयक को लेकर कुछ भी कहें, उन्हें यह तो समझना ही होगा कि हर देश को यह तय करने का अधिकार है कि कौन लोग उसके नागरिक बन सकते हैं और कौन नहीं?

टकराव की स्थिति

बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता सरकार के बीच तल्खी कम होती नहीं दिख रही। इस बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जब टिप्पणी की तो राज्यपाल भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने ममता बनर्जी का नाम लिए बिना निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग अपनी जुबान पर लगाम नहीं लगा रहे हैं। इसके बावजूद मैं राज्य में लोगों की सेवा करने से पीछे नहीं हटूंगा। इससे पहले ममता ने धनखड़ का बिना नाम लिए कहा था कि संवैधानिक पदों पर आसीन लोग भाजपा के मुखपत्र बन गए हैं। यही नहीं सुश्री बनर्जी ने धनखड़ पर समानांतर सरकार चलाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया था। राज्यपाल ने सुश्री बनर्जी के इस आरोप पर टिप्पणी करने से इन्कार करते हुए कहा कि क्रिकेट के खेल में हर गेंद को खेलने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग अपनी जुबान का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और उस पर लगाम नहीं लगा रहे। मैं लोगों की सेवा करना जारी रखूंगा। राज्यपाल ने कहा कि उनके बयानों को पूरी तरह समझे बिना किसी को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। इससे पहले धनखड़ और राज्य सरकार के बीच 'बुलबुल' चक्रवात के कारण हुई तबाही के लिए राहत वितरण को लेकर नए सिरे से आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया था। धनखड़ ने 600 किलोमीटर की यात्रा के लिए राज्य सरकार से हेलीकॉप्टर सेवा देने का अनुरोध किया था, लेकिन हेलीकॉप्टर मुहैया कराने की अनुमति देने का अनुरोध ठुकरा दिया गया। राज्य सरकार ने एक हफ्ते में दूसरी बार इस तरह का अनुरोध अस्वीकार किया है। धनखड़ शुक्रवार सुबह एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने फरक्का गए थे। कहा जा रहा है कि राज्य सरकार से हेलीकॉप्टर के लिए अनुरोध काफी समय रहते किया गया था, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं मिला। तृणमूल कांग्रेस ने राज्यपाल की यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर की जरुरत पर सवाल उठाते हुए इसे बेतुका और जनता के पैसे का दुरुपयोग करार दिया था। यही नहीं राज्यपाल के खिलाफ सिंगुर में तृणमूल समर्थकों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया था। राज्यपाल गो बैक के नारे भी लगाए गए थे। इतना नहीं राज्यपाल पर स्वास्थ्य राज्यमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य से लेकर शिक्षामंत्री पार्थ चटर्जी तक ने टिप्पणी की है। ऐसे में लग रहा है कि आने वाले समय में राज्यपाल और सरकार के बीच तल्खी और बढ़ सकती है। ऐसा इसलिए, क्योंकि आगामी वर्ष नगर निकाय का चुनाव होना है।

> ममता ने धनखड़ का बिना नाम लिए कहा था कि संवैधानिक पदों पर आसीन लोग भाजपा के मुखपत्र बन गए हैं

प्रदूषण नियंत्रण पर निराशाजनक रवैया

संजय गुप्त

केंद्र और राज्यों को यह समझने की सख्त जरूरत है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए उनकी ओर से बहुत कुछ किया जाना शेष है

अवधेश राजपूत

उत्तर भारत में वायु प्रदूषण के बढ़ते प्रकोप के कारण लोगों की सेहत के लिए भयंकर स्थिति पैदा हो गई है, लेकिन उससे निजात मिलने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। इसका एक कारण सरकारी तंत्र की घोर उदासीनता है। शायद इसी रवैये के चलते बीते दिनों शहरी विकास मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति की ओर से प्रदूषण को लेकर बुलाई गई बैठक में कई विभागों के अधिकारी पहुंचे ही नहीं। सरकारी तंत्र के ऐसे रवैये के लिए एक हद तक केंद्र सरकार भी जिम्मेदार है। इस समिति में 30 संसद सदस्य भी हैं, लेकिन बैठक में समिति के अध्यक्ष सहित कुल चार सदस्य ही पहुंचे। इस रवैये की आलोचना ही की जा सकती है, लेकिन सारा दोष इस समिति पर भी नहीं मढ़ा जा सकता, क्योंकि जिन्हें प्रदूषण से निपटने में राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखानी चाहिए वे उसका परिचय देने से इन्कार कर रहे हैं। यह किसी से छिपा नहीं कि प्रति वर्ष अक्टूबर और नवंबर के महीने में जब मौसम बदलता है तब पराली का धुआं, धूल के कण या वाहनों के उत्सर्जन से वातावरण इस कदर प्रदूषित हो जाता है कि लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। चूंकि वायु प्रदूषण को लेकर कोई भी राजनीतिक दल संजीदा नहीं दिखता इसीलिए समय के साथ स्थिति लगातार विकराल होती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में उच्चतम न्यायालय की डांट-फटकार और एनजीटी की सख्ती के बाद जो कदम उठाए गए हैं उससे स्थिति में थोड़ा-बहुत तो सुधार आया है, लेकिन उसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। सच्चाई यही है कि मीडिया में तमाम चर्चा और आम लोगों में जागरूकता के बाद भी ऐसे कदम नहीं उठाए जा सके हैं जिससे वायु प्रदूषण पर लगाम लगती दिखे।

अक्टूबर में जब उत्तर भारत के तापमान में कमी आनी शुरू होती है तभी पंजाब और हरियाणा में पराली जलनी शुरू होती है। इस पराली का धुआं, सड़कों की धूल, वाहनों का उत्सर्जन आदि मिलकर आसमान मे स्मॉग पैदा करते हैं। यह स्मॉग या तो तेज हवा से दूर होता है या फिर बारिश से। वायुमंडल को दूषित करने में पराली दहन एक बड़ा कारण है। मूलतः यह पराली धान की फसल का अवशेष होती है। पंजाब और हरियाणा के किसान इसे जलाना पसंद करते हैं। वे वर्षों से ऐसा करते चले आ रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में जैसे-जैसे धान का रकबा बढ़ रहा है वैसे-वैसे पराली जलने से पर्यावरण को होने वाला नुकसान भी बढ़ रहा है। पराली जलाने का काम पंजाब, हरियाणा के साथ-साथ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भी होता है। चूंकि सर्दियां आते ही पश्चिम की तरफ से हवा चलने लगती है इसलिए पाकिस्तान से लेकर पंजाब, हरियाणा में जलने वाली पराली का सारा धुआं दिल्ली और आसपास के आसमान पर छाकर स्मॉग का रूप ले लेता है।

जैसे हाल के समय में पंजाब और हरियाणा में धान की खेती का रकबा बढ़ा है वैसे ही दिल्ली और आसपास किस्म-किस्म के निर्माण कार्यों में तेजी आई है। इसके चलते निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल की मात्रा बढ़ी है। इसी के साथ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले वाहनों के उत्सर्जन की मात्रा में भी वृद्धि हुई है। इसकी वजह यही है कि दिल्ली-एनसीआर में वाहनों की संख्या बढ़ी है। इसका कारण दिल्ली-एनसीआर में आबादी का घनत्व ज्यादा होना है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का एक कारण दशहरे और दिवाली में पटाखों का इस्तेमाल भी है। हालांकि धीरे-धीरे उनका इस्तेमाल कम हो रहा है, लेकिन बेहतर होगा कि उनका इस्तेमाल और कम किया जाए।

हालांकि वायु प्रदूषण जितना दिल्ली को त्रस्त करता है उतना ही उत्तर भारत के अन्य शहरों को भी, लेकिन दिल्ली के प्रदूषण की ही चर्चा ज्यादा होती है। उच्चतम न्यायालय हो या एनजीटी अथवा केंद्र सरकार, उनकी ओर से तभी सक्रियता दिखाई जाती है जब दिल्ली-एनसीआर का प्रदूषण खबरों का हिस्सा बनता है। पता नहीं क्यों यह देखने से इन्कार किया जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलना इसलिए कम नहीं हो रहा है, क्योंकि किसान धान की खेती करना पसंद कर रहे हैं। इसका कारण मुफ्त बिजली देने की नीति और धान की सरकारी खरीद है। मुफ्त बिजली के कारण किसान भूजल का जमकर दोहन करते हुए धान की फसल इसलिए उगाते हैं, क्योंकि उसकी सरकारी खरीद का भरोसा रहता है। पराली जलाने का सिलसिला इसलिए भी नहीं थम रहा, क्योंकि उसके निस्तारण के सही उपाय नहीं किए जा सके हैं।

समझना कठिन है कि हमारे नीति-नियंता इससे अनजान क्यों बने रहे कि पराली का धुआं पर्यावरण को घातक क्षति पहुंचा रहा है? चूंकि किसानों को खेत खाली करके उस पर गेहूं बोने की जल्दी रहती है इसलिए वे पराली जलाना बेहतर समझते हैं। पराली न जलाने के एवज में किसानों को एक निश्चित राशि देने की मांग न तो पंजाब सरकार पूरी कर सकी और न ही हरियाणा सरकार। वे केंद्र सरकार का मुंह देखती रहीं। इस वर्ष हरियाणा ने तो पराली दहन रोकने के लिए जब तक कुछ कदम उठाए तब तक तमाम पराली जल चुकी थी। पंजाब सरकार एक तरह से हाथ पर हाथ धरे बैठी रही।

हालांकि वायु प्रदूषण को लेकर शहरों में जागरूकता आई है, लेकिन ग्रामीण भारत में स्थिति जस की तस है। यह सही है कि मोदी सरकार के आने के उपरांत एलपीजी सिलेंडर का वितरण बढ़ाए जाने के कारण चूल्हों का इस्तेमाल कम हुआ है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी कोयले और लकड़ी का इस्तेमाल खाना बनाने में किया जा रहा है। बेहतर हो कि प्रदूषण से बचने के लिए वैसी ही ठोस पहल हो जैसी एक समय सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली में हुई थी और उसके इसके तहत दिल्ली में सीएनजी बसों को अनिवार्य करने के साथ कारखानों को बाहर किया गया था।

एक समय था जब दिल्ली-एनसीआर में सरकारों के साथ तमाम पर्यावरणविद् भी दूषित होते पर्यावरण की अनदेखी ही कर रहे थे। यह तब था जब पराली को प्रदूषण की वजह बताया जा रहा था। दैनिक जागरण इसमें अग्रणी था। वायु प्रदूषण को लेकर आंखें तब खुलीं जब राष्ट्रमंडल खेलों की तैयारी के दौरान दिल्ली के पर्यावरण को लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने चिंता जतानी शुरू की। इसके बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने यह कहना शुरू किया कि वायु प्रदूषण का कारण हरियाणा, पंजाब में पराली जलना है। प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने इस वर्ष भी सम-विषम योजना पर अमल किया, लेकिन यह योजना एक सीमा तक ही प्रभावी दिखती है। इसका एक कारण इस योजना से दोपहिया वाहनों को बाहर रखा जाना है। ऐसे आधे-अधूरे उपाय राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी को ही प्रकट करते हैं। दुर्भाग्य से यह कमी राज्य सरकारों और उनकी विभिन्न एजेंसियों के साथ केंद्र सरकार में भी दिखती है। उन्हें यह समझने की सख्त जरूरत है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए उनकी ओर से बहुत कुछ किया जाना शेष है।

response@jagran.com

सत्ता का न्यूनतम साझा कार्यक्रम

हास्य-व्यंग्य

संतोष त्रिवेदी

जन सेवकों ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम में सत्ता के अलावा सब कुछ न्यूनतम करने का संकल्प ले लिया है

सरकार बिल्कुल बनते-बनते रह गई। इस बीच सियासी जानकारों ने कहा कि यदि मौसमी धुंध को सम-विषम मिलकर साफ कर सकते हैं तो सरकार बनाने की धुंध क्यों नहीं साफ की जा सकती? सत्ता के लिए यदि सम विषम बन सकता है तो विषम सम क्यों नहीं? फिर नए दोस्तों को पुराने दाग धोने का लंबा अनुभव है। ताजा-ताजा लड्डू खाने वालों ने तो केवल कुर्सी के लिए ही पुरानी दोस्ती का 'त्याग' किया है। जब 'उनके' साथ थे तो भी कुर्सी के लिए थे। इसीलिए इन्होंने कुछ अजूबा नहीं किया। वैसे भी जो दोस्ती फायदा न दे, उसे बनाए रखने में नुकसान ही है। आखिर राज्य के 'व्यापक हित' को देखते हुए 'नई दोस्ती' में न्यूनतम सहमति यह बनी कि 'जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी।' इसमें वे नंबर एक, नंबर दो और नंबर तीन पर सहमत हुए। फिर सिद्धांत और नैतिकता को 'फेंट' कर 'न्यूनतम साझा कार्यक्रम' का विलयन बना जिसे कभी भी राज्य-हित में उड़ेला जा सकता है। फिलहाल आपसी 'सौदे' सॉरी मसौदे का एक 'अविश्वसनीय' फुटेज हमारे हाथ लगा है। 'जनहित' में हम उसे यहां लीक कर रहे हैं।

नंबर एक ने बड़ी और पायेदार कुर्सी की ओर अंगुली करते हुए कहा, 'हम इस पर कोई समझौता नहीं कर सकते। रात की छोड़िए, दिन में भी दस बार हम इसी का सपना देखते हैं। हमारी ओर से न्यूनतम कार्यक्रम यही है कि सरकार की बागडोर हमारे हाथ में हो। सत्ता से ऐसा भावनात्मक जुड़ाव जानकर नंबर दो ने सहानुभूतिपूर्वक सुझाया, 'दरअसल हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ भी वही 'फिफ्टी-फिफ्टी' खेलो। आखिर अपने पुराने साथी के साथ तो तुम इसके लिए तैयार ही थे। हम नए भी हैं और तुम्हारे हितैषी भी। इससे यह भी साबित होगा कि तुम हमें उतना ही प्यार करते हो, जितना सत्ता से।'

नंबर एक ने तुरंत अपना दावा जारी रखा, 'देखिए, राज्य के लोग चाहते हैं कि हमारे नेतृत्व में 'सत्यवचनी सरकार' बने। 'न्यूनतम साझा कार्यक्रम' में सत्ता के अलावा हम सब कुछ न्यूनतम करने का संकल्प लेते हैं। सिद्धांत और नैतिकता जैसी बाधाओं को हम पहले ही पार कर चुके हैं। हमारे मन में 'पुराना प्यार' उमड़े, इसके पहले ही इस लोकतंत्र का कुछ कर डालो।' लोकतंत्र का नाम सुनते ही नंबर तीन को थोड़ी कसमसाहट हुई। पहलू बदलते हुए उसने अपनी बात रखी, 'लोकतंत्र के प्रति चिंतित होकर ही हम साथ आए हैं। वरना तुम्हारे साथ खड़े होने में भी हमें परेशानी है, पर क्या करें! होटलों में लंबे समय तक हम किसी जनसेवक को बांधकर नहीं रख सकते। वे सभी जनसेवा के लिए मचल रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमें उचित सेवा का हिस्सा मिले। साथ ही तुम थोड़ा 'हिंदुत्व' हल्का करो, हम थोड़ा 'सेक्युलरिज्म' एडजस्ट करेंगे। इससे हमारे सेक्युलर चेहरे पर थोड़ी खरोंच तो आएगी, पर सत्ता सारे घाव भर देती है। हमारी ओर से यही न्यूनतम है। रही बात अधिकतम की तो उसका हिसाब 'नंबर दो' देखेंगे। उनकी 'बारगेनिंग पावर' जबरदस्त है। वह चाहें तो टेस्ट खेलें या फिफ्टी-फिफ्टी। ऐसे मुश्किल वक्त में तो हम 'ट्वेंटी-ट्वेंटी' में भी खुश हैं।' सबकी नजरें अब 'नंबर दो' पर टिक गईं। तभी नंबर दो ने कहा, 'अभी इसमें कुछ 'मिसिंग' है। थोड़ा किसान, थोड़ा नौजवान डालते हैं। फिर भी कुछ कमी है तो वह नंबर तीन बताएंगे।'

'हां, मुझे अभी याद आया कि जो भी मलाईदार विभाग हैं, उनका बंटवारा सेहत के हिसाब से हो। ऐसा न हो कि जिन्होंने कभी मलाई नहीं चखी, उनको ज्यादा मिल जाए। इससे उनकी सेहत बिगड़ सकती है। और हां, हमारी युति के बारे में एक जरूरी बात। हमारे पास अब नंबर एक का 'हिंदुत्व', नंबर दो का 'राष्ट्रवाद' और तीसरे नंबर की 'धर्मनिरपेक्षता' है। इससे एक 'डेडली कांबिनेशन' बनेगा। हम समय-समय पर इसमें संशोधन भी करते रहेंगे।' इतना सुनते ही नंबर एक ने राहत भरी सांस ली। तब 'फिर शपथ कब ग्रहण करें?' इस उत्साह पर नंबर दो ने पानी फेरते हुए कहा, 'अभी केवल 'कॉमन मिनिमम प्रोग्राम' बना है, सरकार नहीं। वह तभी बनेगी जब हमें निमंत्रण मिलेगा।' इसी बीच हमें मालूम पड़ा कि सरकार बनाने के लिए 'असली' नंबर एक ने अपना दावा नहीं छोड़ा। उनका कहना है कि 'प्रोग्राम' किसी का बने, सरकार वही बनाएंगे।

response@jagran.com

तथ्य-कथ्य

महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा और शिवसेना का चुनाव दर चुनाव प्रदर्शन

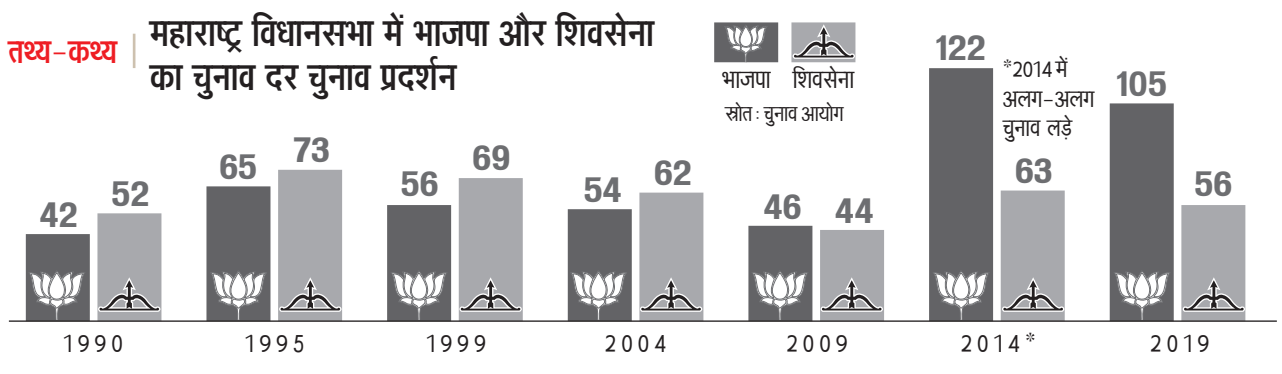

ऊर्जा

मानव प्रवृत्ति

यदि किसी कार्य के दौरान परिणाम सकारात्मक होते है तो हम तुरंत उसका श्रेय लेने लगते हैं। इसके उलट यदि परिणाम नकारात्मक हो तो उसके लिए तमाम बहानों की सूची भी तैयार कर ली जाती है। प्रायः मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा होता है कि यदि कुछ अच्छा हुआ है तो वह सिर्फ उसके कारण ही हुआ है और यदि कहीं कुछ बुरा हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी औरों की है। दोषारोपण करने की इस प्रवृत्ति के चलते हम कब अपना नुकसान कर बैठते हैं, यह खुद हमें ज्ञात ही नहीं हो पाता।

क्या होगा यदि हम अपनी उपलब्धियों का श्रेय सुपात्रों को दे देंगे तो क्या घट जाएगा? इसके विपरीत विफलताओं की जिम्मेदारी स्वयं लेने लग जाएं तो व्यक्तित्व के विकास में मदद मिलेगी। अपनी असफलताओं को स्वीकारने की शक्ति मनुष्य में सीखने की संभावनाओं को जन्म देती है। हम या तो स्वयं गलती करके सीखते हैं या दूसरों की गलती को उदाहरण के तौर पर देखकर अनुभव प्राप्त करते हैं। महात्मा गांधी स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रत्येक सफलता का श्रेय देश की जनता और कार्यकर्ताओं को समर्पित करते थे और यदि कोई आंदोलन विफल होता तो उसके लिए स्वयं को दोषी मानते। ऐसा करके ही वह महान बने।

ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसे ठोकर न लगी हो। यह संसार ऐसे तमाम लोगों की सफलता की कहानी का प्रत्यक्षदर्शी है जिनकी सफलता अनेक ठोकरों की बुनियाद पर ही खड़ी हुई है। जीवन में डिग्री प्राप्त कर लेने पर यह बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। यहां संपूर्ण कोई भी नहीं है, सब ही अपनी क्षमता और मेहनत के आधार पर पूर्ण प्रयास करते है। जीवन ताउम्र चलने वाली पाठशाला के समान है, जहां नित नए ज्ञान की प्राप्ति होगी। किंतु यदि हम तटस्थ हो गए कि हमें तो सब पहले से ही आता है तो यह तटस्थता नया सीखने और समझने की संभावनाओं का अंत कर देगी। इसलिए स्वयं के भीतर के शिष्य भाव का जीवित होना आवश्यक है ताकि हम विफलताओं को स्वीकारते हुए सफलता के पथ पर अग्रसित हो सकें।

सौरभ जैन

समुद्र से मिले बड़े संकेत

मुकुल व्यास

इस शोध से दूसरे ग्रहों और चंद्रमाओं पर जीवन मिलने की उम्मीद जग गई है जहां समुद्र और ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं

वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र की गहराइयों में पाए जाने वाले जलतापीय छिद्रों ने पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए आदर्श परिस्थितियां निर्मित की थीं। समुद्री तल की दरारों से पानी रिसकर पृथ्वी के मैंटल (पर्पटी से नीचे वाला भाग) में पहुंचा जहां मैग्मा (गर्म द्रव्य) ने उसे ऊंचे तापमान पर गर्म करके विशाल कुदरती चिमनियों के जरिये वापस समुद्र में फेंका। ये चिमनियां जलतापीय छिद्रों पर बनती हैं। एक प्रयोग में सभी छिद्रों में पाई जाने वाली गर्म और क्षारीय परिस्थितियों को दोहराने पर प्रोटोसेलों अथवा प्राथमिक कोशिकाओं का निर्माण हुआ। प्रोटोसेल को जीवन निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई माना जाता है।

'नेचर इकोलॉजी' पत्रिका में प्रकाशित शोध रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ऊष्मा और क्षारता जीवों के जन्म के लिए न सिर्फ उपयोगी है, बल्कि आवश्यक भी है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (यूसीएल) में बायोकेमिस्ट्री के प्रोफेसर और इस अध्ययन के प्रमुख निक लेन ने कहा कि जीवन कब और कैसे शुरू हुआ, इस बारे में तरह-तरह के सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। पानी में पाए जाने वाले जलतापीय छिद्रों को जीवन की शुरुआत के लिए सबसे उपयुक्त स्थल माना जाता है। अब नए अध्ययन ने अपने ठोस प्रायोगिक प्रमाण के साथ जीवन उत्पत्ति के इस सिद्धांत को नया बल प्रदान कर दिया है। छिद्रों के मुख पर समुद्र का पानी धरती की पर्पटी के खनिजों के संपर्क में आता है। इससे हाइड्रोजन से युक्त गर्म और क्षारीय माहौल निर्मित होता है। इस प्रक्रिया में खनिजों से भरपूर चिमनियां बनती हैं जिनमें क्षारीय और अम्लीय द्रव्य होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक क्रिया के लिए ऊर्जा यहीं से मिलती है। दोनों गैसों के बीच रासायनिक क्रियाओं से जटिल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है।

यूसीएल के नेतृत्व में शोधकर्ताओं द्वारा खोजे गए विश्व के प्राचीनतम जीवाश्मों का उद्गम इसी तरह के समुदी जलतापीय छिद्रों से हुआ था। अध्ययन में शामिल शोधकर्ताओं का कहना है कि उनके प्रयोग के निष्कर्षों से दूसरे ग्रहों और चंद्रमाओं पर जीवन मिलने की उम्मीद जग गई है जहां समुद्र और ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं। कुदरती रूप से पाए जाने वाले साधारण यौगिकों से प्रोटोसेल बनाने के पिछले प्रयोग सिर्फ ठंडे और स्वच्छ जल में ही सफल हो पाए थे। ये प्रयोग बहुत ही नियंत्रित परिस्थितियों में किए गए थे। यह पहला अवसर है जब शोधकर्ता जलतापीय छिद्रों जैसे माहौल में खुद-ब-खुद असेंबल होने वाले प्रोटोसेल निर्मित करने में सफल रहे हैं।

उन्होंने पाया कि ऊष्मा, क्षारता और लवण से प्रोटोसेल निर्माण में अवरोध नहीं पैदा होता, बल्कि मदद मिलती है। कार्बन की लंबी कड़ियों वाले अणुओं को प्रोटोसेल की संरचना में जुड़ने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है। अध्ययन के लेखक डॉ. सीन जॉर्डन का कहना है कि पिछले अध्ययनों में खामियां थीं। जबकि इसमें विभिन्न फैटी एसिड्स और फैटी अल्कोहल मिश्रण से प्रोटोसेल बनाने की कोशिश की। यह तरीका पहले नहीं आजमाया गया था।

(लेखक विज्ञान मामलों के जानकार हैं)

क्या से क्या हो गया

महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुख्य रूप से राज्य की राजनीति तक सीमित शिवसेना के लिए मौजूदा सूरतेहाल में क्या संभावना बनती दिख रही हैं। हालांकि इसकी पड़ताल तो काफी लंबा विषय है, लेकिन फिलहाल यह तय हो गया है कि महत्वाकांक्षा अंधी होती है। जिस तरह कांग्रेस और राकांपा की ओर से शिवसेना पर लगातार अपनी विचारधारा के साथ समझौता करने की शर्त थोपी जा रही है, उसे देखते हुए शिवसेना के साथ पहचान का संकट खड़ा हो सकता है। यही नहीं कभी पार्टी में बाला साहेब ठाकरे के सबसे नजदीकी रहे राज ठाकरे के उदय का कारण भी बन सकता है। ऐसे में शिवसेना के अंदर का ही एक धड़ा परेशान है। भाजपा के साथ भागीदारी यानी दो हिस्सेदारी। अब तीन की हिस्सेदारी भी झेलनी होगी और विचारधारा को भी तिलांजलि देनी होगी। यह तो वही बात हो गई कि फिफ्टी-फिफ्टी की तमन्ना रखने वालों को अब कहीं ट्वेंटी-ट्वेंटी पर न टिकना पड़े।

सक्रियता से बेचैनी

राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनने के बाद उप-मुख्यमंत्री बने सचिन पायलट अब फिर से सक्रिय हैं। सोशल मीडिया पर

राजरंग

उनकी सक्रियता पहले की तरह दिखने लगी है। पूरे प्रदेश में घूमकर पायलट जन संवाद कर रहे हैं। इसी जन संवाद से ही उन्होंने पूरे प्रदेश में अपनी पहचान कायम की थी, लेकिन प्रदेश में उनकी जन यात्राओं और सोशल मीडिया पर सक्रियता ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे में खलबली मचा दी है। हर कोई इस बात को लेकर परेशान है कि सरकार तो बन गई अब आखिर उप-मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का खेमा न केवल इसका जवाब जानने में जुटा है, बल्कि इसका तोड़ तलाशने में सक्रिय है।

खोखली एकजुटता

राजनीति के खेल भी बड़े निराले हैं। अधिकांश मौकों पर जो बाहर दिखाई देता है, भीतर से हकीकत कुछ और ही दिखाई देती है। कुछ यही हाल विपक्षी गोलबंदी का है। बीते पांच वर्षों में संसद के प्रत्येक सत्र से पहले कांग्रेस विपक्षी दलों में एकजुटता की ताल ठोंकती रही है, मगर अपवाद छोड़ दें तो एकजुटता की गूंज हकीकत से दूर ही रही है। राफेल सौदे विवाद में तो कांग्रेस अपने घटक दलों तक को साध नहीं पाई। राफेल पर सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को मिली ताजा क्लीन चिट के बाद तो विपक्षी दलों को इस मुद्दे पर साथ लाना कांग्रेस के लिए मेढक तौलने से कम नहीं साबित हो रहा। सरकार को घेरने के लिए विपक्षी खेमे के दल उसकी दलीलों पर विचार का आश्वासन तो देते हैं, मगर बात जब इसे संसद सत्र में उछालने की आती है तो उनके सियासी संवाद की लाइन ही बंद हो जाती है। पार्टी की बेचारगी का आलम यह है कि इस मुद्दे पर वह विपक्षी एकजुटता का खुलकर दावा भी नहीं कर पा रही। यानी अपनी सियासी मंजिल पर पहुंचने के लिए फिलहाल दोनों तरफ के रास्ते बंद हैं।

उत्तराधिकारी की परीक्षा

लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा में भी बीते दिनों नेतृत्व परिवर्तन हो गया। स्थापना से लेकर हाल तक पार्टी की कमान संभालने वाले केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने पार्टी की अध्यक्षता अपने बेटे और लोकसभा सदस्य चिराग पासवान को सौंप दी। बिहार में भी राज्य इकाई की बागडोर पासवान ने अपने भतीजे प्रिंस राज के हाथ में दे दी। इससे पहले यह जिम्मेदारी पासवान के भाई पशुपति पारस के पास थी। एक तरह से कहा जाए तो फिलहाल बिहार की दो पार्टियों राजद और लोजपा का नेतृत्व पूरी तरह युवाओं के हाथ आ गया है, लेकिन जिस तरह लालू प्रसाद की गैर मौजूदगी में राजद का जलवा घटने लगा है तो यह सवाल भी पूछा जा रहा है कि क्या पासवान के बिना लोजपा आगे बढ़ पाएगी। पासवान की सबसे बड़ी खूबी है तालमेल बैठाना जिसमें युवा पीढ़ी अभी उतनी पारंगत नहीं दिखती।

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।